ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 390-392

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक प्रभाव

निरपेन्द्र कुमार सिन्हा

असि0 प्रो0– समाजशास्त्र विभाग, चौ0चरण सिंह पी.जी.कॉलेज, हैवरा–इटावा (उ0प्र0) भारत।

Received- 05.08.2020, Revised- 09.08.2020, Accepted - 13.08.2020 E-mail: - nirpendra.kumarsinha@gmail.com

***सारांश :** 'वैश्वीकरण एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जिसके तहत क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति का समन्वय विनियम के वैश्विक नेटवर्क सा हो गया है। जबसे वैश्वीकरण और उदारवाद का दौर आरम्भ हुआ है, दुनिया ने बड़ी तेजी से प्रगति की है। फौर्ब्स की सूची में अमीरों की संख्या में लगातार वृद्धि, पाँच से दस करोड़ प्रतिमाह वेतन पाने वाले मेधावी युवकों को देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन इस प्रगति में बहुत कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो आने वाले समय में जटिल समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। आज की कुछ सामाजिक–आर्थिक समस्याओं में इसकी झलक देखी जा सकती है, जिनका सीधा सरोकार इन्हीं आर्थिक विकासों से है।"*

कुंजीभूत शब्द– वैश्वीकरण, क्षेत्रिय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, समन्वय विनियम, वैश्विक, उदारवाद, तरक्की, प्रोद्योगिकी।

भारत में वैश्वीकरण कोई नयी प्रक्रिया नहीं है वरन् 17वीं शताब्दी से यह उपनिवेशवाद के रूप प्रारम्भ हुई जिसके अगुआ इंग्लैण्ड एवं फ्रांस जैसे देश रहे। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि 1980 के दशक के बाद से अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों ने आर्थिक मंदी से उबरने और अपने उत्पादों की बिक्री हेतु विश्व के अन्य देशों की बाजार–व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की दृष्टि से उदारीकरण की नीति, मुक्त बाजार व्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था तथा प्रौद्योगिकी के एकीकरण की नीति के तहत प्रारम्भ की, उसी के परिणामस्वरूप वैश्वीकरण का जन्म हुआ।

वैश्वीकरण का विचार 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की देन है, जो विभिन्न राष्ट्रों की सत्ता, स्वायत्ता तथा कल्याणकारी कार्यों एवं उदारवादी समाजों, के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिये एक नवीन चुनौती बनकर उभरा है तथा जिसका राष्ट्रों विशेष रूप से विकासशील एवं अर्द्धविकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण राष्ट्र–राज्यों की स्वायत्ता एवं सम्प्रभुता के विकास के मुद्दों के संदर्भ में सिकुड़ रही है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विश्व व्यापार संगठन तथा, बहुराष्ट्रीय निगमों, पर राष्ट्रीय संगठनों द्वारा लादी गयी शर्तों एवं दिशा–निर्देशों ने जहां एक ओर लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर राज्यों की प्रभुसत्ता को भी सीमित करने का प्रयास किया है।

विकास के तमाम हंगामों के बावजूद भारत में आर्थिक सुधारों के इन वर्षों में 1990 की तरह ही प्रत्येक तीसरा भारतीय भीषण दरिद्रता की हालत में जीता रहा है। इससे भी बदतर स्थिति कई अन्य विकासशील देशों में है। यही वजह है कि नोग चोम्सकी जैसे विचारक ने उदारीकरण के औचित्य पर ही सवाल खड़े किये हैं।1

भारतीय राष्ट्र–राज्य अपने स्वातन्त्र्य एवं गणतंत्र की आधी से अधिक सदी देख चुकी है। इस दौरान औपनिवेशिक विरासत में मिली विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिये अनेक योजनायें बनाई गई, पर इन्हें पूरा न किया जा सका। समाज में मँहगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार बढ़ते गये और आम आदमी का जीवन दूभर होता चला जा रहा है। विडम्बना यह है कि आज इन विकट समस्याओं से निजात दिलाने के नाम पर 'आर्थिक सुधारों' के एक भंवरजाल में देश को ढकेल दिया गया है और आजादी के लगभग चार दशकों तक चली 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' (Mixed Economy) को तिलांजली देकर, सार्वजनिक क्षेत्र के विध्वंस निजीकरण एवं विदेशी–पूँजी निवेश का 'भैरव राग' अलापा जा रहा है।

अमेरिका ने अपनी साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी प्रकृति के द्वारा लैटिन अमेरिकन देशों को अपनी जागीर समझते हुये वहां के लोगों के उत्पीड़न एवं शोषण के कारनामों को छिपाने के लिये एक नयी शब्दावली "वैश्वीकरण" को गढ़ा तथा संसार में इसे एक अवधारणा के रूप में सर्वप्रथम प्रेषित कर दिया। इस प्रकार अमेरिका द्वारा प्रस्तावित "वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण" की अवधारणा वास्तव में अमेरिका की साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों का पर्याय है। भूमण्डलीकरण के माध्यम से विकासशील देशों को नियंत्रण में रखने तथा अपना प्रभाव स्थापित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक (W.B) तथा विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) को इस प्रकार प्रभावित किया कि–

– विकासशील देशों में सरकारी स्कूल, कालेज तथा अस्पताल की फीस बढ़वा दी।

– बिजली तथा पानी की दरों में कई गुना वृद्धि करवा दी।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

अनेक कारखाने बन्द करवा दिये।

– राशन की व्यवस्था चौपट कर दी।

– कमजोर तथा गरीबों को बेसहारा बना दिया।

– महिलाओं को भी हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया।

वैश्वीकरण (भूमण्डलीकरण) की अवधारणा का उदय सर्वप्रथम 1990 में 'राबर्टसन' महोदय के एक लेख से हुआ, जिसका शीर्षक था "मैपिंग ग्लोबल कन्डीशन"। 'ग्लोबलाइजेशन ऐज द सेन्ट्रल कान्सेप्ट' का संकलन 'फीदर स्टोन' द्वारा सम्पादित पुस्तक 'ग्लोबल कल्चर' में हुआ। इस लेख में वैश्वीकरण के विश्लेषणात्मक तथा आनुभविक तथ्यों को स्पष्ट किया गया है।

भारत में वैश्वीकरण का आरम्भ 1991 में हुआ, तब पी.बी. नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह, वित्तमंत्री थे। यह नये आर्थिक युग का सूत्रपात था। इसमें जो अर्थव्यवस्था स्थापित हुई वह 'संघीय बाजार व्यवस्था' बन गयी। इससे राज्यों को यह अधिकार मिल गया कि केन्द्रीय योजना व्यवस्था के अन्तर्गत वे अपनी वित्तीय स्थिति में परिवर्तन कर सकते है। इस व्यवस्था में सुधार आता है या खराबी इसके लिये राज्य ही उत्तरदायी होंगे। यह नयी व्यवस्था एक प्रकार से 'नियंत्रण अर्थव्यवस्था' (कमांड इकोनामी) से संघीय अर्थव्यवस्था (फेडरल इकानामी) में बदल गयी। इस प्रकार आर्थिक वैश्वीकरण का सूत्रपात सरकारी स्तर पर सन् 1991 से हुआ।

एक प्रसिद्ध पत्रिका 'इन्टरनेशनल सोश्योलाजी' के अनुसार वैश्वीकरण को समझने के लिये स्टाकहोम में स्वीडन के विदेश मंत्रालय के सहयोग से सन् 1998 में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। जिसमें वैश्वीकरण के विविध पक्षों पर बहस हुई।

सामाजिक प्रभाव– वैश्वीकरण ने सम्पूर्ण विश्व को एक धुरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह विभिन्न राष्ट्रों–राज्यों की राजनैतिक सीमाओं के आर–पार सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक लेन–देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबन्धन का प्रवाह है। विश्व अर्थव्यव्था में आया खुलापन, आपसी जुड़ाव एवं परस्पर निर्भरता के फैलाव को वैश्वीकरण कहा जा सकता है। वैश्वीकरण 'बसुधैव कुटुम्बकम्' के आदर्श पर चलने वाली प्रक्रिया के तेज विस्तार से विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया है। आज वैश्वीकरण प्रत्येक क्षेत्र का मुख्य विषय बन गया है, क्योंकि इसने समाज के प्रत्येक क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित किया है।

वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ सम्पूर्ण विश्व को एक वैश्विक गाँव (Global Vilage) के रूप में देखना है। 'ग्लोबल विलेज' की अवधारणा मार्शल मैक्लुहान की है। यह कोई नई अवधारणा नहीं है। पहले भी शक्तिशाली देश अपने राज्यों, साम्राज्यों और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिये नये तरीकों का उपयोग करते थे। वर्तमान में अमरीकी–संस्कृति विश्व संस्कृति की एकमात्र दावेदार बन गयी है। इसने दूसरे देशों की सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के निष्कंटक प्रसार से यूरोपीय देश भी परेशान है। 1995 में फ्रांस ने अमरीका के विश्व प्रसिद्ध टी0वी0 सीरियल 'बेवाच' पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। लेकिन यह प्रतिबन्ध ज्यादा दिन कायम नहीं रह सका। क्योंकि वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया ने राज्य की सम्प्रभुता को बहुत हद तक कम किया है। राष्ट्र राज्य की शक्ति समय के साथ क्षीण होती जा रही है। निर्बाध केबुल चैनलों के द्वारा सारे कार्यक्रम दूर–दराज के देशों में करोड़ो व्यक्तियों के द्वारा देखे जा रहे है।

आर्थिक प्रभाव– वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र मे हो रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रवाह तेज हो रहा है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप वैश्विक साझा बाजार की उत्पत्ति हुई है। एक ऐसा साझा बाजार जिसमें वस्तु, सेवा एवं पूँजी का स्वतंत्रतापूर्वक आदान–प्रदान हो रहा है। अर्थव्यवस्था में कई तरह की रूकावटें दूर होने से भूमण्डलीकरण का रास्ता साफ हुआ है। व्यापार के क्षेत्र में खुलापन आया है और विदेशी निवेश के प्रति उदारता बढ़ी है साथ ही वित्तीय क्षेत्र में भी उदार नीतियां अपनाई जा रही है। यातायात और संचार क्षेत्र में आयी क्रान्ति ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। जेट विमान, कम्प्यूटर उपग्रह और सूचना तकनीकी की वजह से देश काल की सीमायें समाप्त हो गयी हैं। औद्योगिक संगठनों में नयी प्रबन्ध व्यवस्थाओं के विकास ने भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त अमेरिका की राजनीतिक प्रभुता ने भी वैश्वीकरण को बल प्रदान किया है।

वैश्वीकरण एक बड़े स्तर पर सुधारवादी नीति सम्बन्धी प्रक्रिया है। वैश्वीकरण से सम्बन्धित चार बातें प्रमुख हैं:–

1. व्यापार सम्बन्धी रूकावटों एवं सीमाओं को समाप्त करना जिससे कि वस्तुओं का आदान–प्रदान स्वतंत्र रूप से हो सके।
2. ऐसे वातावरण को तैयार करना जिससे पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह राष्ट्र राज्यों के बीच बना रहे सके।
3. तकनीकी के स्वतंत्र आवगमन के लिये वातावरण को तैयार किया जाना।
4. विकासशील अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिये। जिसमें विश्व के

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

विभिन्न देशों में श्रमिकों के लिये आवागमन सुलभ हों।

वस्तुतः वैश्वीकरण से विकासशील राष्ट्रों की औद्योगिक प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ा है। विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता के समक्ष ये विकासशील राष्ट्र प्रतिस्पर्द्धा करने में असमर्थ रहे हैं। परिणामस्वरूप उनके घरेलू उद्योग बन्द होते जा रहे है। प्रो0 योगेन्द्र सिंह के अनुसार अधिकांश सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक वैश्वीकरण का क्रान्तिकारी पक्ष संचार के क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। रेडियों, टेलीविजन, कम्प्यूटर, नेटवर्क्स, सेटेलाइट द्वारा, पेजिंग सेवायें, टेलीफोन, सेलफोन, फैक्स, इलेक्ट्रानिक मेल, इण्टरनेट, वेब आदि संचार प्रणाली बैंकिग, व्यापार तथा प्रबन्धन व्यवहार में क्रांति उत्पन्न कर रही हैं। दूरसंचार की इस नई प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण समय, दूरी संस्कृति के प्रतीकवाद की धारणा अर्थ के नए रूपान्तरण के तहत चल रहे हैं। इसका स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय, संस्कृति पर प्रभाव बहुआयामी है तथा यह इनका एकीकरण कर सकता है। इस प्रकार से ये परिवर्तन समाज के सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकीय विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभावों को निमन संदर्भ में देखा जा सकता है:–

1. बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
2. पेटैंट प्रणाली और औषधियों एवं दवाइयों पर प्रभाव।
3. कृषि में पेटेन्ट या पेटेन्ट जैसा संरक्षण।
4. व्यापार सम्बन्धित निवेश उपाय और इनका भारत पर प्रभाव।
5. टैक्सटाइल्स एवं वस्त्र उद्योग पर प्रभाव।
6. वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल।

निष्कर्ष एवं सुझाव:– अतः स्पष्ट है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने परिवर्तन की ऐसी ताकतों को उत्पन्न किया है। जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक, प्रभावों को वैश्विक रूप में परिलक्षित किया जा सकता है। वैश्वीकरण के सन्दर्भ में निम्नलिखित सुझाव है–

1. वैश्वीकरण के दौर में अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन स्वदेशी धरातल पर होना चाहिये।
2. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वामित्व को नियंत्रित करते हुये उनकी गतिविधियों पर निगाह रखनी चाहिये।
3. वैश्वीकरण की उन्नत तकनीक का उपयोग विकास की प्रारम्भिक अवस्था में ही किया जाना चाहिये।
4. ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिये, जिनमें देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
5. समाजिक, आर्थिक विकास के लिये वैश्विक शिक्षा की आवश्यकता है। अतः राष्ट्र के आर्थिक और तकनीकी विकास के लिये ई–शिक्षा (उच्च शिक्षा) आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य होनी चाहिये।

अंततः वैश्वीकरण के सम्बन्ध में गाँधी का यह कथन बहुत प्रासंगिक लगता है कि "मैं यह नहीं चाहता हूँ कि मेरा घर चहारदीवारी व खिड़कियों में कैद हो। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सभी संस्कृतियों की हवायें मेरे घर में स्वाभाविक रूप में आयें, परन्तु मैं यह भी चाहता हूँ। कि हवाओं के थपेड़ों से मेरे पैन न उखड़े और मैं अपनी जमीन पर अडिग खड़ा रहूँ।" अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज वैश्वीकरण पर चिन्तन, मनन और गम्भीर शोध की शिद्दत के साथ आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, रहीस के लेख 'गरीबी निर्धारण का अर्थशास्त्र', योजना, नवम्बर, 2008 पृ0 सं0 47
2. श्रीवास्तव, मंजू, 'डेमोक्रेसी, डबलपमेन्ट एण्ड गवर्नेस इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डाइनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च जर्नल, लोक प्रकाशन विभाग, लखनऊ वि.वि. वोल्यूम 9–10, जनवरी–दिसम्बर, 2001 पृ0 सं0 84
3. पत्रिका, 'इन्टरनेषनल सोश्योलॉजी' अंक–5, 2000
4. राबर्ट्सन के लेख–मैपिंग, ग्लोबल कन्डीशन–ग्लोबलाइजेशन एज, सेन्ट्रल कन्सेप्ट पुस्तक–'ग्लोबल कल्चर,' फीडर स्टोन, 1990 न्यूयार्क
5. सिंह जे.पी., आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, प्रेटिस हाल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 2005 पृ0सं0 206
6. सिंह अशोक कुमार, वैश्वीकरण के युग में जनतंत्र एवं विकास, द यू0पी0 जर्नल ऑफ पालिटिकल साइंस, वोल्यूम–9, जनवरी–दिसम्बर, 2003 पृ0सं0 61
7. सिंहल, एस.सी., उदारीकरण और वैश्वीकरण के विकास पर प्रभाव : तुलनात्मक राजनीति, अग्रवाल प्रकाशन आगरा 2004 पृ0सं0 409
8. फ्राइडमैन थॉमस : ग्लोबलाइजेशन, दि लेक्सस एण्ड दि ओलाइव ट्री न्यूयार्क, फर्रार स्ट्रस जीरॉक्स, 1999 पृ– 110।
9. सिंह योगेन्द्र : कल्चर चेन्ज इन इण्डिया: आईडेन्टिटी एण्ड ग्लोब्लाइजेशन, रावत पब्लि0, जयपुर एण्ड न्यू डेलही, 2003 पृ0 सं0 55

*****

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*